10 हजार करोड़ का फंड बनाया है सरकार ने स्टार्ट-अप्स की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। यह फंड 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में योजना की प्रगति और फंड की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा।

बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने में पिछड़ा बंगाल, उत्तर प्रदेश व बिहार

रिपोर्ट ▶ समग्र शिक्षा के तहत राज्यों को दिए गए थे आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लक्ष्य

बंगाल की प्रगति शून्य, यूपी में 45 हजार की जगह सिर्फ 24 सौ स्कूलों में दिया गया प्रशिक्षण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने की मुहिम को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भारी झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में इसे लेकर जहां कोई काम नहीं हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश भी तय लक्ष्य से पीछे है। यहां 45 हजार स्कूलों के मुकाबले सिर्फ 24 सौ स्कूलों में ही छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा किया है।

स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने पर राज्यों के रुख की जानकारी संसद में पेश रिपोर्ट में सामने आई है। समग्र शिक्षा के तहत 2018-19 में देश के 2.11 लाख स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना था। केंद्र सरकार ने इसके लिए 164 करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय मदद भी दी थी। अकेले उत्तर प्रदेश को इसके लिए 41 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन वह सिर्फ सवा दो करोड़ ही खर्च कर सका। इस योजना के तहत स्कूलों में छठी से बारहवीं तक की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाना है।

योजना में पश्चिम बंगाल के 7730 स्कूल शामिल किए गए थे। राज्य को इसके लिए सात करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए थे। बिहार को करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देते हुए 6065 स्कूलों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि वह सिर्फ 1262 स्कूलों में ही प्रशिक्षण दे पाया। झारखंड का प्रदर्शन बेहतर रहा। उसे 480 स्कूलों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य

छठीं से बारहवीं तक की छात्रओं को दिया जाना है प्रशिक्षण। (फाइल फोटो)

दिया गया था, जबकि उसने 379 स्कूलों में इस काम को पूरा किया है। हरियाणा को 3055 स्कूलों में छात्राओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य दिया गया था। वह सिर्फ 1338 स्कूलों में ही प्रशिक्षण दे पाया। हरियाणा को करीब तीन करोड़ रुपये भी दिए गए थे।

साल में दो बार दी जानी थी ट्रेनिंग : योजना के तहत स्कूलों में साल में कम से कम दो बार एक-एक हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इनमें जूडो-कराटे और मार्शल आर्ट के तहत बचाव से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में प्रतिदिन होने वाले खेलकूद और शारीरिक व्यायाम की गतिविधियों में भी इसे शामिल किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को 'गुड टच और बैड टच' के बारे में भी समझाया जाएगा। प्रशिक्षण में स्थानीय पुलिस से भी मदद लेनी थी। मौजूदा समय में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण सिर्फ सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में दिया जाता है।

बेहद खराब प्रदर्शन वाले राज्यो : पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा।

बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य : उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम ञ और त्रिपुरा।

स्विस बैंकों में जमा है ब्रिटेन का सबसे ज्यादा धन, भारत 74वें स्थान पर

ज्यूरिख/नई दिल्ली, प्रेट्र : स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा धन में कमी आई है और वह 73 वें पायदान से लुढ़ककर 74 पर पहुंच गया है जबकि ब्रिटेन अभी भी टॉप पर बना हुआ है। 2018 में भारत के जमा धन में छह फीसद की कमी रही और जमा रकम लगभग 6757 करोड़ रुपये (955मिलियन स्विस फ्रैंक) रही।

स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में विगत वर्षों में 88 वीं पोजिशन में था, लेकिन गत वर्ष इसमें जबर्दस्त गिरावट आई और वह 15 स्थान नीचे गिरकर 73 पर पहुंच गया था। स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों के मुताबिक जहां तक भारतीयों के स्विस बैंकों में पैसा जमा कराने का मामला है तो उसमें काफी गिरावट आई है। विदेशी ब्रांच के साथ-साथ यह गिरावट भारतीय शाखाओं में भी देखी गई।

शीर्ष पांच में अमेरिका, फ्रांस : आंकड़ों के मुताबिक इस मामले में ब्रिटेन टॉप पर बना हुआ है जहां 2018 के अंत तक

- 2018 में भारतीयों की जमा रकम 6 प्रतिशत घटी
- 2018 में स्विस बैंकों में कुल जमा रकम का 26फीसद हिस्सा ब्रिटेन के लोगों का

स्विस बैंक फाइल फोटो

कुल विदेशी राशि में से 26 फीसद से ज्यादा राशि स्विस बैंकों में जमा है। ब्रिटेन के बाद अमेरिका, वेस्टइंडीज, फ्रांस तथा हांगकांग का नंबर आता है। ये देश अभी भी शीर्ष पांच पर बने हुए हैं। स्विस बैंकों में कुल जमा धन में पचास फीसद इन देशों का है। शीर्ष दस देशों में बहामास, जर्मनी. लक्जमबर्ग, कायमान आइसलैंड तथा सिंगापुर हैं।

रूस, चीन काफी आगे : आंकड़ों के मुताबिक. रूस 20, चीन 22, दक्षिण अफ्रीका 60 तो ब्राजील 65 वें स्थान पर है। भारत से ऊपर जो देश हैं उनमें मॉरीशस(71), न्यूजीलैंड (59), फिलीपींस (54). वेनेजुएला (53). सेशेल्स (52). थाइलैंड (39). कनाडा (36), सऊदी अरब (21), पनामा (18). जापान (16), इटली (15), आस्ट्रेलिया (13),यूएई (12) तथा ग्वेर्नसे आइसलैंड (11) हैं।

पाकिस्तान की जमा राशि भी घटी : जहां तक भारत के पड़ोसी देशों का सवाल है तो पाकिस्तान 82, बांग्लादेश 89, नेपाल 109, श्रीलंका 141, म्यांमार 187 तो भूटान 193 वें स्थान पर है। विगत चार वर्षों में पहली बार पाकिस्तान के स्विस बैंकों में जमा धन में कमी आई है।

भारत की जमा राशि में तेजी से गिरावट : भारत 1996 से 2007 तक शीर्ष पचास देशों में बना हुआ था, लेकिन 2008 से इसमें गिरावट आई और 2008 में वह जहां 55 स्थान पर था, वहीं 2009 और 2010 में 59 स्थान पर पहुंच गया। 2011 में फिर वह 55 स्थान पर पहुंचा तो 2012 में 71 तो 2013 मे वह फिर 58 वें पायदान पर पहुंच गया।

न्यूज गैलरी

शिवसेना से हो सकते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष

नई दिल्ली : लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद राजग के सहयोगी शिवसेना को मिल सकता है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के दौरान लोकसभा को नया उपाध्यक्ष मिलेगा। इस पद को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत दावा कर चुके हैं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष उनकी पार्टी से होना चाहिए। शिवसेना ने इस बात को लेकर राजग सरकार पर दबाव बना रखा है। 18 सांसदों वाली शिवसेना के साथ इस संबंध में दो बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस और बीजद भी इस पद की होड़ में शामिल होने की बात कही गई है, लेकिन दोनों दलों से इससे इन्कार किया है। (एएनआइ)

राफेल टीम आफिस से डाटा चोरी की जांच जारी : जिएग्लर

नई दिल्ली : भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्सांद्र जिएग्लर ने कहा है कि पेरिस में स्थित भारतीय वायुसेना के राफेल परियोजना प्रबंधन टीम आफिस से डाटा चोरी की संभावित जांच चल रही है। नोएडा में एल ओपेरा फ्रेंच बेकरी के उद्घाटन के बाद राजदूत ने कहा, 'अभी जांच जारी है इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह बात पूरे भरोसे से कहना चाहता हूं कि कोई चोरी नहीं हुई है।' राजदूत की इस टिप्पणी से एक दिन पहले साइबर फोरेंसिक टीम ने दावा किया था कि राफेल कार्यालय के कंप्यूटरों से कोई डाटा चोरी नहीं हुई है। रक्षा सूत्रों ने कहा, 'साइबर फोरेंसिक टीम ने पाया है कि सेंध लगाने के दौरान भारतीय राफेल परियोजना प्रबंधन टीम से सेंध लगाने के दौरान कोई डाटा चोरी नहीं हुई है।' वायुसेना को सेंध लगने की जानकारी मिलने के बाद तीन सदस्यीय टीम पेरिस रवाना हो गई थी। (एएनआइ)

तेलंगाना में 2121 करोड़ के बांध को पर्यावरण मंजूरी

नई दिल्ली : सरकारी पर्यावरण समिति ने तेलंगाना के जयशंकर भूपालापैली जिले में गोदावरी नदी पर 2,121 करोड़ रुपये के बांध के निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है। पीवी नरसिम्हाराव कंथनपल्ली सुजाला स्रवंती परियोजना के तहत गोदावरी नदी के ऊपर 23 मीटर ऊंचा और 1,132 मीटर लंबा बांध बनना है। इस बांध के बनने से तीन जिलों जयशंकर भूपालापैली, नालगोंडा और खामम में रबी के मौसम में सिंचाई की सुविधा होगी। इस परियोजना पर पर्यावरण संबंधी शर्तों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की बनाई पर्यावरण समिति ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अंतिम मंजूरी से पहले अपनी सिफारिशें दी थीं। तेलंगाना सरकार इस परियोजना की पर्यावरण मंजूरी के लिए दिसंबर, 2018 में आवेदन किया था। (प्रेट्र)

आकस्मिक मौतों के मामलों में भी अदालत में दाखिल हो जांच रिपोर्ट

माला दीक्षित, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें आकस्मिक और दुर्घटना में होने वाली मौतों के मामलों में भी अदालत में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देने की मांग की गई है। मौजूदा कानून (सीआरपीसी की धारा 174) में ऐसे मामलों में पुलिस के विवेकाधिकार पर है कि वह विधिवत केस दर्ज करे और जांच कर रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करे या सिर्फ प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम या डीएम को देकर केस बंद कर दे। कानून के इस अहम मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

अज्ञात लोगों की आकस्मिक मौत के मामले, जैसे-ट्रेन से कटने या दुर्घटना में हुई ज्यादातर मौतों में पुलिस सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई करती है। इसमें वह घटनास्थल पर जाकर जांच करके रिपोर्ट तैयार करती है और उसे एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सौंप देती है। याचिका में एक ऐसे ही मामले को आधार बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि जालंधर के क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस में काम करने वाले राहुल भाटिया की कथित तौर पर ट्रेन से कट कर मौत हो गई थी। अब उनके माता-पिता पिछले दो वर्षों से उसकी मौत का कारण जानने और मामले की गहराई से जांच के लिए पुलिस और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। याचिका में राहुल भाटिया की मौत की जांच एसआइटी या सीबीआइ से कराने की भी मांग की गई है।

यह याचिका कानून के विद्यार्थी दीपाली वशिष्ठ, प्रतीक राज और अनुराग मणि ने दाखिल की है। दीपाली बताती हैं कि आकस्मिक मौतों के मामलों मे पुलिस एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देती है और इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को देना भी जरूरी नहीं समझती है। वह कहती हैं कि राहुल भाटिया की मौत के कारण की आज तक जांच नहीं हुई। रिपोर्ट में मौत का कारण दुर्घटना दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि देश में रोजाना सैकड़ों लोग सड़क हादसों में अकारण काल का ग्रास बन जाते हैं। दुर्घटनाओं में गंभीर से घायल लोगों को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है।

- सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका, सुनवाई आज
- ऐसे मामलों में पुलिस के विवेक पर है कि वह केस दर्ज करे या नहीं

दिल्ली के रहने वाले थे राहुल भाटिया

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, मूल रूप से दिल्ली के हरिनगर निवासी राहुल भाटिया 15 नवंबर 2017 को दोपहर बाद तीन बजे तक ऑफिस में काम करते हैं। शाम करीब चार बजे जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के पास दो किलोमीटर दूर तक ट्रेन से कटे उनके शव के टुकड़े पुलिस को मिलते हैं। शाम छह बजे दिल्ली में उनके परिवार को उनकी मौत की खबर दी जाती है। दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिजनों को सौंपा जाता है। 19 नवंबर 2017 को जालंधर कैंट पुलिस चौकी सीआरपीसी की धारा 174 में जांच रिपोर्ट सौंप देती है।

अमित शाह, योगी और नड्डा ने सुनी पीएम की मन की बात

नई दिल्ली में रविवार को ककरौला स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात सुनते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सांसद प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और हंसराज हंस। हरि प्रकाश

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम पूरी तरह से तल्लीन हो कर सुना।

आम चुनाव के चलते दो महीने से भी अधिक समय बाद फिर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में रविवार को अमित शाह ने दिल्ली के भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी के साथ यह कार्यक्रम दिल्ली के द्वारका स्थित ककरोला स्टेडियम में सुना। जबकि सीएम आदित्यनाथ ने यह कार्यक्रम मुरादाबाद में सुना। अन्य नेताओं में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रधानमंत्री का अनौपचारिक संवाद सुना।

करनाल में खट्टर ने संवाददाताओं से कहा कि चुनाव जीत के बाद यह हमारे प्रधानमंत्री का पहला मन की बात कार्यक्रम था। उन्होंने कई सामाजिक महत्व के मुद्दों जैसे जल संरक्षण पर गहन चर्चा की। वहीं, पुणे में जावड़ेकर मन की बात पुणेवासियों के साथ मिलकर सुनते रहे।

मोदी का रेडियो कार्यक्रम अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी कैडर को सभी स्तर पर बेहतर रेडियो सेट सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे।

मोदी बोले, गूगल गुरू युग में पढ़ें किताबें

नई दिल्ली, एएनआइ : पीएम मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से किताबें पढ़ने की अपील की। उन्होंने बुके देने के बजाय किताबें भेंट करने की चलन फिर से अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किताबें पढ़कर उन पर परिचर्चा करें कि वह उन्हें क्यों पसंद है। पीएम ने रविवार को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि यह गूगल गुरू का डिजिटल युग है। मैं आपसे अपील करता हूं कि कुछ समय किताब पढ़ने में लगाएं। आपको ऐसा करना बहुत पसंद आएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मोबाइल एप पर किताबें पढ़कर उन पर चर्चा करें। मोदी ने कहा, 'मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कई बार सुना होगा, बुके नहीं किताब। मेरा भी मानना है कि बुके के बजाय किताबें भेंट करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने तो किताबें गिफ्ट करनी भी शुरू कर दी हैं।' उन्होंने उन्हें भेंट की गई 'प्रेमचंद की लघु कहानियों' की याद करते हुए कहा कि उन कहानियों में वर्तमान हालात हैं। उनकी कहानियां मानव भावनाओं में आधारित हैं, जो मुझे अंदर तक छू लेती हैं। ये सदियों पुरानी कहानियां हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी एक कहानी 'नशा' पढ़कर मुझे अहसास हुआ कि यह किस तरह आर्थिक रूप से समाज को खोखला बना रहा है। उनकी एक अन्य कहानी 'ईदगाह' में भी जिंदगी की सच्चाई है। 'पूस की रात' में गरीब किसान की विसंगतियां हैं।

शोध को बढ़ावा देने को खुलेगा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नई शिक्षा नीति में की गई सिफारिश
- प्रासंगिक और सामाजिक रूप से उपयोगी अनुसंधानों को मिलेगी तरजीह

उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने की सरकार की पहल को नई शिक्षा नीति से भी ताकत मिली है। नीति में इसके लिए राष्ट्रीय स्तर का एक अनुसंधान फाउंडेशन बनाने की सिफारिश की गई है। जहां शोध से जुड़े कामों का आकलन और उन्हें बढ़ावा देने जैसे काम होंगे। इनमें प्रासंगिक और सामाजिक रूप से उपयोगी अनुसंधान को प्रमुखता से शामिल करने की सिफारिश की गई है।

नई शिक्षा नीति के प्रस्तावित मसौदे में इसके साथ ही ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों को भी चिन्हित करने पर जोर दिया गया है, जहां मौजूदा समय में शोध कार्यों की गति बेहद सुस्त है। ऐसे में इन संस्थानों को नए सिरे से शोध को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही प्रतिष्ठित शोध संस्थानों से सेवानिवृत्त हो चुके विद्वानों का भी एक ग्रुप बनाने की बात कही गई है, जो समय-समय पर शोध से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी राय देगा।

केंद्र सरकार की प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर का फाउंडेशन शोधकर्ताओं, सरकार, उद्योग और मंत्रालयों के बीच संपर्क का काम करेगा। साथ ही सभी क्षेत्रों में होने वाले शोध कार्यों पर अपनी पैनी नजर भी रखेगा। मौजूदा समय में सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में होने वाले शोध कार्यों का आपस में कोई भी तालमेल नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से विश्वस्तरीय दर्जा रखने वाले संस्थानों का चयन उनके शोध प्रदर्शन को देखते हुए किया जाता है। फिलहाल इस प्रस्तावित नीति को लेकर सरकार अभी लोगों की राय लेने में जुटी है। इसके तहत सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक 31 जुलाई तक अपना मशविरा दे सकते हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पनडुब्बी सिंधुकीर्ति और नौसैनिक पोत आइएनएस शिवालिक का अवलोकन किया। पूर्वी नौसैनिक कमान के दो दिवसीय दौरे में राजनाथ को कमान की परिचालन तत्परता और समुद्री तथा तटीय सुरक्षा के अन्य पहलुओं से अवगत कराया गया। पोत और पनडुब्बी के दौरे में राजनाथ ने चालक दल के सदस्यों से बात की, उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नौसेना की भरिभूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि जवान समुद्री चुनौतियों से निपटने तथा देश के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए सदैव चौकस रहते हैं। एएनआइ

डिग्री अमान्य होने पर इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची कुवैत भेजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों की एक सूची कुवैत प्रशासन को भेजी है। मंत्रालय ने यह कदम खाड़ी देशों द्वारा लिए गए उस निर्णय के बाद उठाया है, जिसमें उसने सिर्फ एनबीए स्वीकृत कोर्सों को मान्यता देने की बात कही थी। बता दें कि इसके चलते आइआइटी ग्रेजुएट सहित हजारों भारतीय इंजीनियरों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है।

दरअसल, पिछले साल कुवैत के मानव संसाधन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि श्रम विभाग तब तक किसी भी अप्रवासी इंजीनियर को वर्क परमिट जारी नहीं करेगा जब तक वे कुवैत इंजीनियर्स सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करते हैं। भारतीय इंजीनियरों को एनओसी तभी जारी होती है जब उनके पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा मान्यता दी गई हो।

मानव संसाधन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल कुवैत गया था। वहां के अधिकारियों से चर्चा के बाद गैर-एनबीए प्रमुख संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सूची कुवैत स्थित भारतीय दूतावास भेजी जा चुकी है।' बता दें कि आइआइटी, आइआइएससी ने अपने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए एनबीए से कभी मान्यता नहीं ली है जबकि कई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआइटी) को भी अपने बीटेक पाठ्यक्रमों के लिए उससे मान्यता नहीं मिली है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

रुकावट

1957 में समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन सचिव ने कराया बंद, 2003 से आंदोलन की शक्ल ले चुकी यह मांग फिर उम्मीदों के मुहाने पर है

अफसर की मनमानी ने छीना था 17 जातियों का हक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- उप्र में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मामला
- साइमन कमीशन की सिफारिश पर हुए सर्वे के आधार पर मिलते थे प्रमाण पत्र

पिछड़ों की हिमायत में आगे रहने की होड़ से 17 जातियों के मुद्दे को सियासी हवा मिल गई है। इन अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए उप्र में सपा और बसपा भी कदम उठा चुकी थी, लेकिन सफलता न मिली। अब भाजपा ने अपने एजेंडे के झोले से यह कार्ड निकाला है। अति पिछड़ों का जो हक लंबे समय से हुकूमत का दरवाजा पीट रहा है, वह तो उनसे एक अफसर की मनमानी ने छीना था। 1957 के पहले तक तो इन सभी जातियों को अनुसूचित प्रमाण पत्र मिलते थे। बहरहाल, 2003 से आंदोलन की शक्ल ले चुकी यह मांग फिर उम्मीदों के मुहाने पर है।

उप्र में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का फैसला योगी सरकार ने लिया है। मामला न्यायालय में चुनौती झेल रहा है और यह केंद्र सरकार तक भी जाना है, मगर इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि यह फैसला नया नहीं, बल्कि स्थिति 'यू-टर्न' वाली है।

इस मुद्दे पर 2003 से आंदोलनरत दलित शोषित वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संतराम प्रजापति के मुताबिक, साइमन कमीशन की सिफारिश पर 1931 में अछूत जातियों का सर्वे (कम्प्लीट सर्वे ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड सिस्टम) हुआ था। तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जेएच हट्टन की रिपोर्ट में 68 जातियों को अछूत माना गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इन्हें विशेष दर्जा दिया गया। इसके बाद भारत सरकार के तत्कालीन सचिव ने सभी राज्यों से उन जातियों की रिपोर्ट मांगी, जो मुख्यधारा से अलग हों। इनमें उप्र की 17 जातियां पाई गईं। इनमें कुम्हार और प्रजापति को शिल्पकार और बाकी 15 को मझवार उपजाति में रखा गया। इन सभी को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिए जाते थे। संतराम ने बताया कि तब इन चिह्नित जातियों की आबादी 23 फीसद थी। 1957 में समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन सचिव ने अपने स्तर से सर्कुलर जारी कर दिया कि यह सूची अब प्रभाव में नहीं है। उन्होंने अपने तर्क दिए, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना लगभग बंद हो गया। फिर 1996 में पूरी तरह रोक लग गई।

यूं चला आंदोलन का सफर

- 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 14 जिलों का सर्वे कराकर केंद्र सरकार को भेजा। सरकार ने पूरे प्रदेश की रिपोर्ट मांगी। तब तक कार्यकाल समाप्त हो गया।
- 11 अप्रैल 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार से प्रस्ताव वापस मांगा। कारण पूछने के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया।
- फरवरी 2013 में अखिलेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन 14 मार्च 2014 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसे खारिज कर दिया।
- इसके बाद प्रस्ताव को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई, जो अभी विचाराधीन है।

यह हैं 17 जातियां : कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी तथा मछुआ।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
राजनीति विज्ञान
(Optional)
पाश्चात्य विचारक से कक्षा प्रारम्भ...
2 JULY 2019 3:00 PM TO 6 PM
सामान्य अध्ययन-II (मुख्य परीक्षा)
राजव्यवस्था
Polity (Mains)
से कक्षा प्रारम्भ
2 JULY 2019 11:30 AM TO 2:00PM
301, 307 TOP FLOOR, SATIJA HOUSE, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58